



सोने की कलम

Email - sonekikalam@gmail.com

आर.एन.आई. रजि. नं. 52089/91

प्रधान सम्पादक - चेतन गन्धे, 9893157809

वर्ष - 33 अंक - 40

(साप्ताहिक)

इन्दौर, 14 नवंबर से 20 नवंबर 2024, गुरुवार

मूल्य 1 रुपये

पृष्ठ 4

मोदी प्रदेश के दो जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का करेंगे लोकार्पण - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

♦ भोपाल, सोने की कलम।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 नवम्बर को बिहार के जमुई में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 15 अगस्त 2016 को देश के विभिन्न प्रदेशों में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई थी। छिंदवाड़ा शहर में स्थित श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय भवन का निर्माण 40 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया



है। यहां क्यूरेशन का कार्य जनजातीय कार्य विभाग के अधीन बना संस्थान द्वारा किया गया है। इसका निर्माण पुराने जनजातीय संग्रहालय की उपलब्ध भूमि पर ही किया गया है। यह स्थल पंच-पचमढ़ी मार्ग पर स्थित है। संग्रहालय के आस-पास कई दर्शनीय तथा जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल भी हैं।

नवीन जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय भवन में 6 गैलरी, एक कार्यशाला कक्ष तथा एक लाइब्रेरी के अलावा कार्यालय के लिये समुचित स्थान भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 800 दर्शकों की क्षमता वाले ओपन एयर थिएटर, शिल्प बाजार

(शिल्पग्राम) एवं ट्राइबल कैफेटेरिया का निर्माण भी यहां किया गया है। इसी परिसर में स्थित पुराने जनजातीय संग्रहालय का नवीनीकरण भी किया गया है, जिसमें जनजातीय संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रादर्श रखे हुए हैं।

नवीन जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में प्रदेश के 9 मुख्य जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम तथा 16 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन एवं जीवंत चित्रण किया गया है। प्रथम गैलरी रानी दुर्गावती को समर्पित की गई है, जिसमें रानी दुर्गावती के जीवन, उनके शासन और उनके बाहरी आक्रमणकारियों से संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा कहा- अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन मामले पर सुनवाई पर बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अपराध की सजा घरवालों की नहीं दी जा सकती है। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। जज अभी फैसला पढ़ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक कदम नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और जज बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला नहीं कर सकती।

सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के दौरान हमने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया है। न्याय के सिद्धांतों और पूर्व में आए फैसलों जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और जस्टिस पुतास्वामी को ध्यान में रखकर हम फैसला करने वाले हैं। जज ने यह भी कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में कानून का शासन बना रहे, लेकिन उसके साथ यह भी समझना होगा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है।



छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार

एक दिन में होगी UPPCS की परीक्षा



♦ लखनऊ, सोने की कलम।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-प्री और आरओ-एआरओ की परीक्षा में वन डे वन डे वन शिफ्ट का मंजूरी दे दी है। प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के चलते आयोग ने गुरुवार को एक बैठक में यह निर्णय लिया है। बता दें कि छात्रों ने पिछले चार दिनों से प्रयागराज में आयोग कार्यालय के सामने नॉर्मलाइजेशन और दो शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे। बता दें कि प्रयागराज में हजारों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि आयोग द्वारा कराई जाने वाली स्टेट पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ/एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में लागू होने वाले 'नॉर्मलाइजेशन' को खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही कई शिफ्टों में होने वाली इन परीक्षाओं को एक ही शिफ्ट में कराने की मांग छात्र कर रहे थे। आयोग की तरफ से इन दोनों परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद से ही छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति है - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

उमरिया जिले में विगत डेढ़ साल में 3 हजार 490 से अधिक को मिला आयुष्मान योजना का लाभ

♦ भोपाल, सोने की कलम।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति है, जो गरीबों और वंचितों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रही है। इस योजना से आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है, साथ ही राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में भी योजना सहायक सिद्ध हो रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को उनकी बीमारी के इलाज के लिए एक नया संबल प्रदान किया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है और राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार हो



रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समग्र स्वास्थ्य के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में स्वास्थ्य और

सुरक्षा का संचार हो रहा है। उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत के ग्राम बड़ागांव निवासी सुश्री रानी कोल को कैंसर बीमारी से लड़ने में आयुष्मान भारत योजना ने संबल प्रदान किया। रानी कोल को जब कैंसर का पता चला, तो उनका परिवार इलाज के लिए परेशान हो गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज कराना उनके लिए असंभव सा लग रहा था। आयुष्मान योजना से रानी कोल का सफल इलाज हुआ और आज वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके परिवार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस योजना के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आयुष्मान भारत योजना उनके जैसे लाखों गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।

जो व्यक्ति, स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता

संपादकीय

समाज की एकजुटता ही उसकी शक्ति है

समाज की एकजुटता उसकी ताकत होती है, और यह ताकत तब और भी प्रगति करती है जब लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। रजत समाज, जो कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में समृद्ध है, ने हमेशा एकजुटता और सामूहिक प्रयासों से ही अपनी शक्ति को प्रमाणित किया है। आज के दौर में, जब सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तब इस एकजुटता की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है।

रजत समाज के लोग अपनी विविधताओं के बावजूद एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, या रोजगार के अवसरों की बात हो, समाज की प्रगति तब ही संभव है जब उसके लोग एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करें। सामूहिक शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे समाज की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में देखा जा सकता है, जहाँ लोग अपने मतभेदों को भुलाकर समाज के कल्याण के लिए एकजुट होते हैं।

इस समाज के भीतर छिपी हुई एकजुटता ही उसे अपनी दिशा निर्धारित करने की शक्ति देती है। हम जितना अधिक एक दूसरे का साथ देंगे, उतनी ही अधिक हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम होंगे। समय की माँग है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को संजोते हुए, एक नए जोश और उमंग के साथ समाज की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करें।

समाज की एकजुटता में ही उसकी असली शक्ति निहित है। जब लोग अपने समुदाय, संस्कृति और सामाजिक हितों के लिए एकजुट होते हैं, तो उनका सामूहिक प्रयास किसी भी चुनौती से बड़ी होती है। यही एकजुटता हमें अपने समाज को और अधिक समृद्ध और सशक्त बनाने में मदद करेगी।

नए साल में बुजुर्गों को मिलेगा सीनियर सिटीजन कांफ्लेक्स

इंदौर। इंदौर शहर में बुजुर्गों के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) द्वारा पहली बार सीनियर सिटीजन कांफ्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। नए साल में इस कांफ्लेक्स की सुविधा मिल सकेगी। यहां पर आधुनिक सुविधाएं जुड़ाई गई हैं। सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हुए फिजियोथेरेपी सेंटर, योगा कक्ष, डॉक्टर रूम और जरूरी वस्तुओं की दुकानें भी बनाई गई हैं। इमारत का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और अब फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। आईडीए ने 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन कांफ्लेक्स का निर्माण करीब दो साल पहले शुरू किया था। निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सभी काम आने वाले माह तक पूरे कर लिए जाएंगे। बहुमंजिला कांफ्लेक्स में 32 फ्लैट एक और दो बीएचके के बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग के लिए भी तल मंजिल पर सुविधा दी गई है। कांफ्लेक्स में दो आधुनिक लिफ्ट और अन्य सुविधाएं रहेंगी।



चेतन गंधे
9893157809
सम्पादक

पीएम मित्रा पार्क के लिए मिल गए 6 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

◆इन्दौर, सोने की कलम।

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को जो पीएम मित्रा पार्क प्रोजेक्ट दिया है उसमें चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने कल संभागयुक्त दीपक सिंह पहुंचे। भैंसोला में 2177 एकड़ जमीन पर यह पार्क विकसित किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1670 करोड़ की राशि खर्च होगी और केंद्र सरकार ने दो चरणों में 500 करोड़ रुपए देना तय किया है।

इस पार्क में अभी तक टेक्सटाइल और गारमेंट्स से जुड़ी 19 बड़ी इकाइयों ने रुचि दिखाई है और लगभग 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में ये पीएम मित्रा पार्क मंजूर किए हैं, जिसमें कपास से धागा, वस्त्र निर्माण और उनकी बिक्री, निर्यात सहित सभी कार्य एक ही स्थान पर हो सकेंगे। संभागयुक्त सिंह ने कार्यों को तय समयसीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर इंदौर रेंज के आईजी अनुराग, कलेक्टर प्रियंक मिश्र, पुलिस अधीक्षक मनोजकुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री एमपीआईडीसी एसएस टेनुवा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संभागयुक्त सिंह ने पीएम मित्रा पार्क के तहत किए जाने वाले कार्यों एवं अब तक हुए विकास कार्यों की स्थिति और

संभागयुक्त नेकिया चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन, 2177 एकड़ भैंसोला की जमीन पर हो रहा है पार्क विकसित, 1670 करोड़ रुपए होंगे प्रोजेक्ट पर खर्च

प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 एफ विजन (फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन) को साकार करने के लिए पीएम मित्रा पार्क विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में सात पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं। इनमें मध्यप्रदेश में भी एक पीएम मित्रा पार्क शामिल है। इसमें कपास से धागा, धागे से वस्त्र निर्माण और तैयार वस्त्र की बिक्री एवं निर्यात का कार्य एक स्थान पर होगा। मध्यप्रदेश में पीएम मित्रा पार्क इंदौर संभाग के धार जिले में बदनावर के पास स्थित भैंसोला में लगभग 2177 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इस स्थान को पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए सर्वाधिक अनुकूल मानते हुए इसे चयनित किया गया है।

पार्क की भूमि एमपीआईडीसी के आधिपत्य में है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1670 करोड़ रुपए है। इस पार्क के विकास के लिए केंद्र सरकार 2 चरण में 500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। पार्क में मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति में मिलने वाले समस्त लाभ उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही भारत सरकार ने 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को टर्नओवर का 3 प्रतिशत (अधिकतम 15 करोड़ एवं 30 करोड़) तीन वर्ष तक प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस पार्क के लिए केंद्र और मध्यप्रदेश शासन के मध्य एक एसपीवी का गठन किया गया है, जिसमें राज्य शासन की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत एवं केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। टेक्सटाइल पार्क में निवेश के लिए 19 इकाइयों ने रुचि व्यक्त की है। इनके द्वारा करीब 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दो लाख रोजगार प्राप्त होंगे। टेक्सटाइल एवं गारमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अशिक्षित और अनुकूल व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के भरपूर अवसर होते हैं। इनमें 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल होती हैं।

पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा समाजसेवी डॉ. भाग्यश्री खरखडिया सम्मानित

◆इन्दौर, सोने की कलम।

पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली समाजसेविका डॉ. भाग्यश्री खरखडिया को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में पश्चिम रेलवे के महामंत्री श्री आर. जी. काबर, वेस्टर्न रेलवे के अध्यक्ष श्री शरीफ खान पठान, सहायक मंत्री श्री बीके गर्ग, और पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अध्यक्ष श्री प्रताप गिरी एवं श्री राकेश दुबे सहित कई सम्माननीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. खरखडिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि उन्हें आज



सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, और यह सम्मान उनके जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण है। यह मेरी अत्यधिक सौभाग्य की बात है कि मुझे इस सम्मान से नवाजा गया, और मैं इसे अपनी विशेष स्मृति के रूप में हमेशा संजोकर रखूंगी। इस सम्मान का मेरे लिए गहरा अर्थ है, क्योंकि यह न केवल मेरी मेहनत और समर्पण की पहचान है, बल्कि मेरे परिवार के लिए भी गर्व का

कारण है। महत्वपूर्ण यह भी है कि मेरे पति, श्री नवीन खरखडिया, जो भारतीय पश्चिम रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उन्हें सम्मानित करने वाली इस संस्था से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। इस सम्मान को पाकर मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ और भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करती रहूंगी।

पीएम मित्रा पार्क के लिए मिल गए 6 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

◆इन्दौर, सोने की कलम।

केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को दी गई पीएम मित्रा पार्क परियोजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कल संभागायुक्त दीपक सिंह पहुंचे। भैंसोला में 2177 एकड़ भूमि पर इस पार्क का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 1670 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए दो चरणों में 500 करोड़ रुपये देने की योजना बनाई है। इस पार्क में अब तक टेक्सटाइल और गारमेंट्स से संबंधित 19 बड़ी इकाइयों ने रुचि दिखाई है और 6000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने देश के सात राज्यों में पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। इस पार्क में कपास से धागा, वस्त्र निर्माण और उनकी बिक्री व निर्यात सभी कार्य एक ही स्थान पर किए जाएंगे।

संभागायुक्त दीपक सिंह ने निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर इंदौर रेंज के आईजी अनुराग, कलेक्टर प्रियंक मिश्र, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री एमपीआईडीसी एसएस टेनुवा समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।



संभागायुक्त ने पीएम मित्रा पार्क के तहत चल रहे कार्यों और उनके विकास की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5% विजन (Farm to Fiber to Factory to Fashion to Foreign) के तहत विकसित किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश में इस पार्क के लिए 2177 एकड़ भूमि पर काम शुरू किया है, जिसे एमपीआईडीसी के अधीन विकसित किया जा रहा है। पार्क की अनुमानित लागत 1670 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये की राशि दो चरणों में प्रदान करेगी। इस पार्क के विकास में मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति के तहत सभी लाभ उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही, भारत सरकार ने 100

संभागायुक्त ने चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया, 2177 एकड़ भैंसोला की जमीन पर हो रहा है पार्क का विकास, 1670 करोड़ रुपये होंगे इस परियोजना पर खर्च

करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इकाइयों को तीन वर्षों तक टर्नओवर का 3 प्रतिशत (अधिकतम 15 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये) की छूट देने का भी निर्णय लिया है।

इस पार्क के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक एसपीवी (स्पेशल पर्पस व्हीकल) का गठन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की 51 प्रतिशत और केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

अब तक 19 इकाइयों ने इस टेक्सटाइल पार्क में निवेश के लिए रुचि दिखाई है, जो 6000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही हैं। इस पार्क से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दो लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर

की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अशिक्षित और अकुशल व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के पर्याप्त अवसर होते हैं, और इसमें 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं रोजगार पा सकती हैं। इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी यह पार्क महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसे उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया है, जिनमें रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। यही कारण है कि देश के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग में मध्यप्रदेश को लेकर एक उत्साहजनक माहौल है।

ज्ञात हो कि हाल ही में इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित कई निवेशकों ने रुचि दिखाई थी। इस पार्क का निर्माण बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देशों के कपड़ा उद्योगों से सुझाव लेकर किया गया है। इस पार्क में कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, रंगाई, छपाई और परिधान निर्माण जैसी गतिविधियां की जाएंगी। इस पार्क के माध्यम से कपड़ा क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत कर भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कपड़ा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है।

उज्जैन से बस से आए थे लूटेरें, पुलिस ने नानाखेड़ा बस स्टैंड पर बढ़ाई जांच

◆इन्दौर, सोने की कलम।

तुकोगंज क्षेत्र में लाखों की लूट के आरोपी उज्जैन से बस के जरिए इंदौर पहुंचे थे और फिर बस से ही वापस उज्जैन चले गए। अब पुलिस का ध्यान पूरी तरह से उज्जैन पर केंद्रित हो गया है और वहां कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं।

पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि तुकोगंज थाना क्षेत्र के रेसकोर्स रोड पर कमलेश अग्रवाल, पिकेश और उनके परिवार के अन्य सदस्य से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बाइक सवार बदमाशों ने उज्जैन से बस पकड़कर इंदौर की यात्रा की थी। इन बदमाशों ने शहर में पांच स्थानों पर लूट की कोशिश की, लेकिन अंततः यह वारदात रेसकोर्स रोड पर हुई। वारदात के बाद, वे अपनी बाइक छोड़कर, उसी बस से वापस उज्जैन लौट गए।

हालांकि, नानाखेड़ा बस स्टैंड पर पुलिस को कोई महत्वपूर्ण फुटेज नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। पुलिस ने अब बाहर के कैमरों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा, डीसीपी हंसराज सिंह ने बताया कि पुलिस उज्जैन में लॉज और होटलों की भी जांच कर रही है, ताकि आरोपियों के ठहरने के बारे में जानकारी मिल सके।

इसके अलावा, पुलिस महाकाल मंदिर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, क्योंकि पहले भी अपराधी उज्जैन में महाकाल दर्शन के बहाने अपराध करने आ चुके हैं। उस दिन भी सोमवार था, और यह भी संभव है कि अपराधियों ने मंदिर के दर्शन किए हों। पुलिस के अनुसार, दोनों लूटेरे गाड़ी से गिरने के बाद कुछ दूरी तक भागे थे, और इस दौरान एक लूटेरे का जूता भी गिर गया था, जिसे दूसरे लूटेरे ने हाथ में उठा लिया था। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, और अब पुलिस उस फुटेज की जांच कर रही है।

खजराना गणेश मंदिर में लड्डू प्रसाद अब नई आकर्षक पैकिंग में मिलेगा

◆इन्दौर, सोने की कलम।

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भक्तों को चढ़ाने के लिए बेचे जाने वाले लड्डू प्रसाद की पैकिंग अब पूरी तरह बदलने जा रही है। वर्तमान में मंदिर परिसर में लड्डू 450 से 500 प्रति किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, जबकि मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 320 प्रति किलो की दर पर शुद्ध बेसन के लड्डू भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बावजूद भक्तों की संख्या इस काउंटर से कम देखी

जा रही थी, क्योंकि पैकिंग आकर्षक नहीं थी।

इसे ध्यान में रखते हुए, मंदिर प्रबंध समिति ने पैकिंग को आकर्षक बनाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में खजराना गणेश मंदिर का लड्डू अब शहर की मशहूर मिठाई की दुकान भंवरी लाल उत्तम भोग जैन मिठाई भंडार जैसी आकर्षक पैकिंग में बेचा जाएगा। भंवरी लाल मिठाई भंडार इस पैकिंग के लिए निशुल्क सहायता प्रदान करेगा और लड्डू बनाने में भी



पूरा सहयोग देगा। मंदिर प्रशासन ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर

को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए लड्डू को अब कागज की थैलियों और पुष्टे के डब्बों में पैक किया जाएगा। पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि पैकिंग का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और कलेक्टर के निर्देश पर इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बहुत जल्द इस नई पैकिंग में लड्डू प्रसाद भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम भक्तों को एक नई अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ लड्डू प्रसाद की बिक्री को भी बढ़ावा देगा।

इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन से टोल सरकार वसूलेगी, मेटेनेस कंपनी के जिम्मे

15 साल तक निर्माण करने वाली एजेंसी को करना होगा रखरखाव

◆इंदौर, सोने की कलम।

इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वहां से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूली तो प्रदेश सरकार करेगी, लेकिन उसकी साज-संभाल रोड बनाने वाली कांटेक्टर कंपनी को 15 साल तक करना होगा। अब मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) को यह तय करना है कि टोल वसूली का फॉर्मूला क्या हो।



एमपीआरडीसी करती रहेगी। उसे हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर सड़क चौड़ीकरण का ठेका दिया गया है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 1692 करोड़ रुपये आंकी गई है। इंदौर-देवास सिक्स लेन हाईवे और इंदौर बायपास के बाद यह तीसरा हाईवे होगा, जिसकी चौड़ाई सिक्स लेन होगी। हालांकि तीनों में से सिर्फ इंदौर-उज्जैन हाईवे ही स्टेट हाईवे है, जिसका साज-संभाल एमपीआरडीसी के पास है। बचे दोनों हाईवे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी आफ इंडिया के पास हैं।

कांटेक्टर कंपनी को रखरखाव के लिए नियमानुसार राशि का भुगतान

नहीं बदलेगी दोनों टोल प्लाजा की जगह

एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक राकेश जैन ने बताया कि इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन रोड प्रोजेक्ट के तहत दो टोल प्लाजा जस के तस रहेंगे। वर्तमान फोर लेन रोड पर एक टोल प्लाजा इंदौर के पास बारोली और दूसरा उज्जैन के पास निनौरा में है। दोनों यथावत रहेंगे। केवल वहां की चौड़ाई सिक्स लेन के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी 15 साल तक हाईवे संभालेगी। टोल वसूली का काम एमपीआरडीसी अलग से नीति तय कर दूसरी एजेंसी को सौंपेगी।

हिंदुत्व पर बड़ा युवा सम्मेलन धीरेंद्र शास्त्री इंदौर आएंगे



लालबाग में आध्यात्मिक सेवा संस्थान के बैनरतले होगा आयोजन, हजारों युवाओं को लाने का लक्ष्य

◆इंदौर, सोने की कलम।

इस महीने की आखिरी तारीख को इंदौर में एक ऐतिहासिक हिंदू युवा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हजारों युवाओं के जुटने का अनुमान है। हिंदुत्व पर आधारित इस सम्मेलन में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री युवाओं को संबोधित करेंगे। यह आयोजन हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करना है।

सम्मेलन का आयोजन लालबाग में स्थित हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के बैनर तले किया जाएगा, जिसका विषय रंग-रंग हिंदू मेरा परिचय रखा गया है। यह आयोजन न केवल युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इस संस्थान द्वारा भारतीय सभ्यता की महत्वपूर्ण धरोहरों को भी संजोने का कार्य किया जाएगा। सम्मेलन के प्रमुख आयोजक और प्रचार प्रमुख जवाहर मंगवानी ने बताया कि

मेला 28 नवंबर से शुरू होगा। इस दिन शाम को एक भव्य नारी शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न संस्थाओं और अखाड़ों से जुड़ी 5000 बालिकाओं का जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद, शाम 6 बजे लालबाग में संतों के आशीर्वाचन के साथ मेले का उद्घाटन होगा। सम्मेलन के कार्यक्रमों में 29 नवंबर को एक आचार्य वंदन कार्यक्रम होगा, जिसमें 100 विद्यालयों के 500 शिक्षक और 1000 विद्यार्थी पादपूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे महिला समूह द्वारा स्तोत्र पाठ किया जाएगा। शाम 8 बजे 20 कॉलेजों के बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। 1 दिसंबर को विशेष रूप से मातृ-पितृ वंदन और मातृत्व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5000 गर्भवती महिलाओं को संतों द्वारा आशीर्वाचन दिया जाएगा। समापन सत्र 2 दिसंबर को होगा, जिसमें विभिन्न एनजीओ के डायरेक्टर्स, मठ-मंदिर संचालक और जाति-बिरादरी प्रमुखों को आमंत्रित किया जाएगा। इस विशाल आयोजन के माध्यम से हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, और उम्मीद है कि यह सम्मेलन युवाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार करेगा।

चंद्रभागा क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या से राहत

सात करोड़ लागत से नया नाला निर्माण कार्य शुरू होगा



◆इंदौर, सोने की कलम।

चंद्रभागा हनुमान मंदिर से लेकर कलालकुई मस्जिद तक की क्षेत्रीय जल निकासी प्रणाली में वर्षों पुरानी अव्यवस्था और क्षतिग्रस्त नाले के कारण हर बारिश में गंभीर जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही थी।

इस समस्या के समाधान हेतु नगर निगम ने पिछले दो-तीन वर्षों में एक प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण कार्य प्रारंभ करने में छह माह का समय लग गया। अब, नगर निगम ने उक्त क्षेत्र में सात करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नाले के पुनर्निर्माण और सड़क निर्माण कार्य को दो-तीन दिन में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। नगर निगम

अधिकारियों के अनुसार, परियोजना के पहले चरण में पुराने नाले को पूरी तरह से तोड़कर नया, विस्तृत और मजबूत नाला बनाया जाएगा। यह नया नाला बारिश के पानी के बेहतर निपटान के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि जल-जमाव की समस्या से बचा जा सके। साथ ही, हनुमान मंदिर से लेकर कलालकुई मस्जिद तक सीमेंट की सड़क का निर्माण भी प्रस्तावित है। बाद के चरण में, आसपास के क्षेत्र में कुछ संरचनात्मक बाधाओं को भी हटाया जाएगा। यह परियोजना स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का प्रतीक है, क्योंकि पहले के नाले की खराब स्थिति और अत्यधिक जल भराव ने लंबे समय तक जीवन को प्रभावित किया था।

उद्योगों के कर्मचारियों के लिए बनेगी टाउनशिप, 1362 फ्लैट बनाए जाएंगे

◆इंदौर, सोने की कलम।

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी-अफसरों को इंदौर और आसपास के शहरों से अपडाउन न करना पड़े, इसलिए मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) उद्योगों के समीप ही आवासीय टाउनशिप तैयार करने की योजना

पर काम कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की मंशा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उसी क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएं ताकि उन्हें कार्यस्थल तक जाने में परेशानी न हो। इसलिए एमपीआईडीसी ने दो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के आवास एवं

शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा है। जिसमें इंदौर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली आवासीय सोसायटियों की तर्ज पर पीथमपुर में टाउनशिप विकसित की जाएगी। पीथमपुर के सेक्टर-1 और 6 में दो टाउनशिप में बनने वाली 22 इमारतों में 1362 फ्लैट तैयार किए जाएंगे।